

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
06.08.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2799 का उत्तर

पूर्वोत्तर रेलवे कनेक्टिविटी परियोजना

2799. श्री दिनेशभाई मकवाणा:

श्री दिलीप शङ्कीया:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान में पूर्वोत्तर रेलवे कनेक्टिविटी परियोजना की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और
- (ख) उक्त रेलवे परियोजना में निवेश की गई राशि का ब्यौरा क्या है और 2024 तक प्रचालनशील हो चुकी रेलवे लाइनों की कुल लंबाई कितनी है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम छोर संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्व आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है, जो चालू परियोजनाओं के थ्रो-फॉरवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित रेल नेटवर्क की लाइन क्षमता को बढ़ाने और संवर्धित करने के लिए, 777 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 12 रेल परियोजनाओं (08 नई लाइनें, 04 दोहरीकरण) को स्वीकृति दी गई है, जिनकी लागत 69,342 करोड़ रुपये है और जो पूरी तरह/आंशिक रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में आती हैं, जिनमें से 278 किलोमीटर लंबाई चालू हो गई है और मार्च, 2025 तक 41,676 करोड़ रुपए का व्यय उपगत किया गया है।

कार्य की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी.)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी.)	मार्च, 2024 तक कुल व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	08	448	113	38,078
दोहरीकरण	04	329	165	3,698
कुल	12	777	278	41,676

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत बजट आबंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	परिव्यय
2009-14	2,122 करोड़ रुपए प्रति वर्ष
2025-26	10,440 करोड़ रुपए (5 गुना)

2009-14 और 2014-25 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले नए रेलपथ की कमीशनिंग (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण) का विवरण निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किया गया नया रेलपथ	कमीशन किए गए नए रेलपथ की औसत लंबाई
2009-14	333 किमी	66.6 किलोमीटर प्रति वर्ष
2014-25	1,840 किमी	167.27 किलोमीटर प्रति वर्ष (लगभग 3 गुना)

2014 से पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णतः/आंशिक रूप से चालू की गई परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1	बोगीबील पुल (92 किमी.)	5820
2	अगरतला- सबरूम (112 किमी.) नई लाइन	3170
3	अगरतला- अकौरा (5 किमी) नई लाइन	865
4	रंगिया- मुरकोंगसेलेक (510 किमी) आमान परिवर्तन	3019
5	कुमारघाट-अगरतला (109 किमी) आमान परिवर्तन	1242
6	कटाखाल-भराबी (84 किमी) आमान परिवर्तन	348
7	लमडिंग-बदरपुर-सिलचर से बदरपुर-कुमारघाट (412 किलोमीटर) आमान परिवर्तन	673
8	लमडिंग- होजाई (45 किमी) दोहरीकरण	410
9	दिगारू-होजाई (102 किमी) दोहरीकरण	1873
10	न्यू बोंगाईगांव-अगथोरी (143 कि.मी.) दोहरीकरण	2048

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णतः/आंशिक रूप से आने वाली कुछ मुख्य परियोजनाएं जो शुरू की गई हैं, वे इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रुपए में)
1	जिरीबाम-इम्फाल (111 किमी) नई लाइन	18562
2	दीमापुर-कोहिमा (82 किमी) नई लाइन	6911
3	भैरबी-सैरांग (51 किलोमीटर) नई लाइन	5521
4	मुरकोंगसेलेक-पासीघाट (27 किलोमीटर) नई लाइन	980
5	न्यू बोंगाईगांव- गोलपारा-गुवाहाटी (कामाख्या) (176 किलोमीटर)	2950

	दोहरीकरण	
6	सरायघाट पुल (7 किमी) दोहरीकरण	1478
7	अलुआबारी-ठाकुरगंज (20 किमी) दोहरीकरण	327
8	अलुआबारी-न्यू जलपाईगुड़ी (57 किमी) तीसरी और चौथी लाइन	1786

इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों, अर्थात् वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष के दौरान, प्रधान मंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत पूर्वोक्त क्षेत्र में पूर्णतः/आंशिक रूप से आने वाले कुल 1790 किलोमीटर लंबाई के 17 सर्वेक्षण (13 नई लाइन और 4 दोहरीकरण) स्वीकृत किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण सर्वेक्षण नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई किलोमीटर में
1	जुब्ज़ा-इम्फाल नई लाइन	150
2	लंका - सिलचर वाया चंद्रनाथपुर नई लाइन	208
3	सैरांग-हबिछुआ (मिजोरम) नई लाइन	223
4	अगथोरी- देकारगांव नई लाइन	130
5	तेजपुर-सिलघाट नई लाइन	40
6	चंद्रनाथपुर-अगरतला दोहरीकरण	244
7	गुवाहाटी-लमडिंग तीसरी लाइन	181
8	न्यू जलपाईगुड़ी- कामाख्या तीसरी और चौथी लाइन	421
9	कटिहार-अलुआबारी तीसरी और चौथी लाइन	145

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के बाद, परियोजना की स्वीकृति के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और आवश्यक अनुमोदन जैसे नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि से मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। चूंकि परियोजनाओं की स्वीकृति एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए सटीक समय-सीमा तय नहीं की जा सकती।

इसी प्रकार, पूर्वोत्तर रेल में स्थित रेल नेटवर्क की लाइन क्षमता संवर्धन के लिए, 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, पूर्वोत्तर रेल पर 20,466 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 1,253 किमी लंबाई की कुल 17 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (08 नई लाइन, 01 आमान परिवर्तन और 08 दोहरीकरण) स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 354 किमी लंबाई चालू हो गई है और मार्च 2025 तक 10,486 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है। सारांश इस प्रकार है:

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी.)	मार्च, 2025 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी.)	मार्च, 2025 तक कुल व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	8	656	48	4042
आमान परिवर्तन	1	56	0	260
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	8	541	306	6184
कुल	17	1253	354	10486

पूर्वोत्तर रेलवे में हाल ही में पूरी की गई परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना	नवीनतम लागत (करोड़ रुपए में)
1	गाज़ीपुर सिटी-तारीघाट नई लाइन (17 कि.मी.)	1766
2	इंदारा-दोहरीघाट आमान परिवर्तन (34 कि.मी.)	213
3	लखनऊ-पीलीभीत आमान परिवर्तन (263 कि.मी.)	1634
4	बलिया-गाजीपुर शहर दोहरीकरण (65 कि.मी.)	650
5	औडिहार-जौनपुर दोहरीकरण (60 कि.मी.)	405
6	मल्हौर-डालीगंज दोहरीकरण (13 कि.मी.)	183
7	रोजा-सीतापुर कैंट-बुढ़वल दोहरीकरण (181 कि.मी.)	2094
8	वाराणसी-माधोसिंह-प्रयागराज दोहरीकरण (120 कि.मी.)	2018
9	ऐशबाग-मानकनगर दोहरीकरण (4 कि.मी.)	82

पूर्वोत्तर रेलवे पर कुछ प्रमुख परियोजनाएं जो शुरू की गई हैं, निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1.	आनंदनगर-घुघुली बरास्ता महाराजगंज नई लाइन (53 किमी)	958
2.	एटा-कासगंज नई लाइन (29 कि.मी.)	389
3.	गोरखपुर कैंट - वाल्मीकिनगर दोहरीकरण (96 कि.मी.)	1121
4.	बाराबंकी - बुढ़वल तीसरी लाइन (27 कि.मी.)	426
5.	मानकपुर - टिकरी दोहरीकरण (28 कि.मी.)	280

पिछले तीन वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष के दौरान, पूर्वोत्तर रेलवे पर 1878 किलोमीटर लंबाई के 46 सर्वेक्षण (5 नई लाइनें, 2 आमान परिवर्तन और 39 दोहरीकरण) स्वीकृत किए गए हैं।

रेल परियोजना/ओं का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन स्वीकृति, उल्लंघनकारी उपयोगिताओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृति, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना/ओं के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, विशेष परियोजना स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य महीनों की संख्या आदि। ये सभी कारक परियोजना के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।
